

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (शिकायत) 10/2022 - 713
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 05.09.2022

विषय:- गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखण्ड के जयनगरा गांव के 80 लोगों को मृत बताकर राशन कार्ड रद्द कर दिये जाने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।

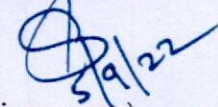
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक-23.08.2022 को "छः साल पहले गांव के 80 लोगों को मृत बता राशन कार्ड रद्द किये, अब ग्रामीण अफसरो को दे रहे हैं जिंदा होने के सबूत" शीर्षक अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुई है। प्रकाशित समाचार में गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखण्ड के खरौंधा पंचायत के जयनगरा गांव के 80 व्यक्तियों को मृत बताकर राशन कार्ड रद्द कर दिये जाने का उल्लेख है। यह भी उल्लेखित है कि इस कारण उन्हें विगत छः वर्षों तक राशन से वंचित रहना पड़ा।

अतः उपरोक्त प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

put-up
23/8/22

पुष्प शिरोड
23/8/22

717
23-08-22

भास्कर खास • लाभुकों ने डीसी से जिंदा साबित करने की लगाई गुहार, जांच के दिए आदेश छह साल पहले गांव के 80 लोगों को मृत बता राशन कार्ड रद्द किए, अब ग्रामीण अफसरों को दे रहे हैं जिंदा होने के सबूत

प्रियरंजन विनोद | कांडी (गढ़वा)

न कोई महामारी आई, न भूकंप आया। न कहीं ज्वालामुखी फटा और न बाढ़ आई, लेकिन सरकारी बाबुओं ने एक गांव के 80 लोगों को एक साथ मृत बता दिया। साथ ही, उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए। 6 वर्षों से ग्रामीणों को न तो सरकारी राशन मिल रहा है और न कोई सुविधा। इनमें दो दर्जन से ज्यादा महिलाएं हैं। सोमवार को अचानक गांव वाले गढ़वा डीसी रमेश घोलप के ऑफिस पहुंचे और उनको अपने जिंदा होने का प्रमाण दिया तो वे भी हैरत में पड़ गए। मामला कांडी प्रखंड की खरौंधा पंचायत के जयनगरा गांव का है। ग्रामीणों ने डीसी से मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग और न्याय की गुहार लगाई है। जिनको मृत बताया गया, कुंती कुंवर, पार्वती देवी, जीरा देशी, सुषमा देवी, मालती देवी, जुगती देवी, आशा देवी, पूनम देवी, सुशीला देवी, तेतरी कुंवर और कलोला देवी आदि शामिल थीं।

ग्रामीण बोले- विभाग के पोर्टल से पता चला कि रिकॉर्ड में हम मृत हैं



कुंती कुंवर, पार्वती देवी, प्रदीप मेहता और प्रवेश मेहता ने बताया कि उन्हें 6 साल से राशन नहीं मिल रहा था। सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। पहले डीलर के पास गए। फिर कांडी प्रखंड कार्यालय पहुंचे। कई दिनों कार्यालय की दौड़ लगाई, लेकिन 6 साल तक किसी ने नहीं बताया। अब ग्रामीणों ने खाद्य आपूर्ति विभाग का पोर्टल देखा तो पता चला कि उन्हें मृत बताया

जा रहा है, यानी सरकारी रिकॉर्ड में वे सभी मर चुके हैं। पोर्टल पर जिंदा ग्रामीणों को मृत देखकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए। मुखिया परीखा पार्सवान, पंचायत समिति सदस्य उर्मिला देवी ने भी प्रशासन को लिखकर दिया है कि सभी जीवित हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गढ़वा जिला अकाल की चपेट में है। ऐसे में सरकारी हाकिमों ने उनसे सुविधाएं छीन ली है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। डीसी ने बीडीओ से तीन दिन मांगी जांच रिपोर्ट : डीसी रमेश घोलप ने कहा कि कांडी बीडीओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार तिवारी से जानकारी मांगी है। उनसे कहा है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर को साथ लेकर बैठें और एक-एक लाभुक की जांच करें। बीडीओ से तीन दिनों में जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है।